सीएम को वैज्ञानिक अहमद मैकेनाइज्ड हैंडवॉश मशीन का डेमो देते हुए।

संक्षिप्त समाचार

वैज्ञानिक शाबिर अहमद ने मैकेनाइज्ड हैंडवॉश मशीन का डेमो दिया

संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष शुक्रवार को वैज्ञानिक शाबिर अहमद ने मैकेनाइज्ड हैंडवॉश मशीन का डेमो दिया। उन्होंने कहा कि यह मशीन कोविड–19 के दृष्टिगत बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन के द्वारा नल एवं साबुन को छुए बिना हाथ धोया जा सकता है। इस मशीन में पानी एवं साबुन का कंट्रोल पांवो से किया जाता है। मशीन में दो पेडल हैं जिनसे आवश्यकतानुसार पानी एवं साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी औसतन लागत लगभग 9,500 रुपए है।

भाजयुमो ने पुलिस, सीपीयू जवानों, पत्रकारों व एनसीसी कैडेटों को किया सम्मानित

संवाददाता देहरादून। कोरोना वायरस कोविड 19 से निपटने के लिए कोरोना योद्धाओं पत्रकारों, पुलिस कर्मचारियों, सीपीयू जवानों, एनसीसी कैडेटों, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवियों को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर, सैनिटाइजर व मॉस्क प्रदान कर सम्मानित किया। घंटाघर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी गौरव पांडे, राष्ट्रीय सह प्रभारी नेहा जोशी व प्रदेश सचिव अंशुल चावला के नेतृत्व में सम्मानित किया गया।

ईसाई समुदाय ने पुलिस के लिए सौंपा मेडिकल का सामान

संवाददाता देहरादून। कोरोना वायरस से लड़ाई में ईसाई समुदाय के तत्वावधान में देहरादून पुलिस को मेडिकल सामान उपलब्ध कराया गया जिसमें सैनिटाइजर, मॉस्क व गलब्ज व साबुन शामिल थे। इस अवसर पर घंटाघर पर एक सादे समारोह के बीच एसपी सिटी श्वेता चौबे की मौजूदगी में समुदाय के लोगों ने पुलिस के लिए मेडिकल सामान उपलब्ध कराया गया और इस अवसर पर कोरोना वायरस से लड़ाई में ईसाई समुदाय भी आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहा है। इस अवसर एसपी सिटी श्वेता चौबे से ईसाई समुदाय के लोगों को आभार व्यक्त किया।

पीडब्ल्यूडी के रिश्वतखोर प्रधान लिपिक को हाईकोर्ट से मिली जमानत

संवाददाता नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान घर परिवार की देखरेख करने के आधार पर रिश्वत लेने के मामले में छह माह से जेल में बंद लोक निर्माण विभाग के प्रधान लिपिक को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। प्रधान लिपिक को विजिलेंस की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय में विडियोकॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई में पहली अंतरिम जमानत मंजूर हुई है।

उत्तराखंड होटलियरों को रेस्क्यू करे सरकारः सुरेन्द्र उनियाल

संवाददाता देहरादून। भारतीय नमो संघ व समाज सेवी सुरेन्द्र उनियाल ने सरकार द्वारा लाक डाउन बढ़ाने के निर्णय लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधान मंत्री व प्रदेश के मुख्य मंत्री से आग्रह किया है कि सरकार लाक डाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है पर देश के विभिन्न शहरों में फसें उत्तराखंड के होटेलियरो की समस्यायों का संज्ञान सरकार ले , जारी पत्र में उनियाल ने चिंता जताई है कि लाक डाउन बढ़ाने से होटियलरो की मुसीबत बढ़ सकती हैं वो राशन पानी, पैसे न होने के कारण भुखमरी की कगार पर है उन्होंने हैदराबाद, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, अहमदाबाद सहित विभिन्न प्रदेशों में फंसे लोगो के रहने खाने व उत्तराखंड रेस्क्यू करने के बाद ही कोई फैसला लेने का आग्रह किया है। सुरेन्द्र उनियाल ने बताया कि हजारों की संख्या में लोग उन्हें फोन कर मदद मांग रहे हैं उनके पास किराए व खाने तक पैसे नही बचे हैं, और वहां का प्रशासन कोई मदद नही कर रहा है किसी प्रकार की अनहोनी हो इससे पूर्व सरकार मानवता को ध्यान में रखते हुए इन उत्तराखंडी हॉटेलियरो की रक्षा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु सिंह तोमर ने बताया सबसे अधिक अहमदाबाद में फसे है उन्होंने 32 पेज की लिस्ट में नाम और नंबर सहित फंसे होटलियर की सूची जारी करते हुए सरकार से रेस्क्यू करने की अपील की।

उत्तराखंड में कोरोना के दो नए मामले आए सामने

कहर

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के दो नए मामले सामने आए हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और भगतसिंह कॉलोनी के बच्चे में कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 39 हो चुकी हैं। हालांकि, दो जमातियों समेत नौ लोग अबतक स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड में दो दिन की राहत के बाद शुक्रवार को कोरोना वायरस के दो नए मामले सामने आए हैं। एक डॉक्टर और बच्चे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद परेशानियां और बढ़ गई हैं। देहरादून में अबतक कोरोना संक्रमण के बीस मामले सामने आ चुके हैं।

इससे पहले गुरुवार को सभी 186 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अबतक एक दिन में जांचे गए सैंपलों की यह संख्या सबसे रही। वहीं, राज्यभर में 62424 लोगों को होम क्वारंटाइन और 1898 संस्थागत क्वारंटाइन हैं। बुधवार की तुलना में नौ हजार से ज्यादा लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। पहले यह संख्या 53000 थी।

बता दें कि इस समय पूरे देश भर में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। इस लिहाज से उत्तराखंड में अभी धीमी गति से टेस्टिंग हो रही है। अभी तक केवल ऋषिकेश एम्स और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ही टेस्टिंग हो पा रही है, जबकि जल्द दून अस्पताल समेत आइआइपी में टेस्टिंग की तैयारी चल रही है। इस लिहाज से गुरुवार को बढ़ी हुई सैंपल जांच की संख्या कम से कम भविष्य की तैयारियों को लेकर एक उम्मीद तो बंधा ही रही है।

एक साल का बच्चा और डॉक्टर कोरोना संक्रमित, 39 पहुंचा आंकड़ा | दून में अबतक कोरोना संक्रमण के बीस मामले

सख्तीः प्रदेश की सभी सीमाओं पर सख्त नजर रखी जा रही है ताकि कोई चोरी छिपे आ–जा न सके।

जमातियों को शरण दी तो होगा मुकदमाः अभी तक खुद सामने न आने वाले जमातियों के साथ इन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। ऐसे लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल, प्रदेश में एक अप्रैल के बाद कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। इनमें सबसे अधिक मामले जमातियों में पाए गए हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने सभी जमातियों को पांच अप्रैल तक खुद सामने आने को कहा था। ऐसा न करने पर छह अप्रैल से इन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इनमें कुछ मुकदमें भी दर्ज हुए हैं। बावजूद इसके कई जमाती ऐसे हैं जो सामने नहीं आए हैं।

शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि अभी भी कुछ जमाती छिपे हुए हैं। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि इन्हें शरण देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में बाहर से आई जमातों और प्रदेश से बाहर गई जमातों के 1423 जमातियों की पहचान हुई है।

उत्तराखंड पुलिस सीएम राहत कोष में देगी तीन करोड़

निर्णय

■ कॉपरेटिव बैंक ने दिए एक लाख 11 हजार

देहरादून। **संवाददाता**

उत्तराखंड पुलिस माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में तीन करोड़ रुपये देगी। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने लगभग तीन करोड़ रुपये स्वैच्छिक योगदान से माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। जिसके अन्तर्गत स्वेच्छा से राजपत्रित अधिकारी तीन दिन एवं अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन देंगे।

मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए पांच लाख रुपयेः ऋषिकेश नारायण भगवान भरत की ओर से महंत अशोक प्रपन्नाचार्य महाराज ने पांच लाख की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट की है। गुरुवार को श्री भरत मंदिर की ओर से पांच लाख रुपये की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को सौंपा गया। भरत मंदिर की ओर से अब तक 600 किट संपूर्ण आवश्यक भोज्य सामग्री की ऋषिकेश के गंगानगर, वाल्मीकि नगर, मायाकुंड, चंद्रेश्वर नगर, आइडीपीएल से लेकर प्रतीत नगर, रायवाला तक जरूरतमंद लोगों को बांटी जा चुकी है। इसके अलावा श्री भरत मंदिर पब्लिक स्कूल की ओर से दस लाख की आर्थिक सहायता कोरोना संकट से लड़ने के लिए दी गई है। इस अवसर पर श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर गोविंद सिंह रावत, एसबीएम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य धीरेंद्र जोशी, रंजन, विनोद आदि उपस्थित थे।

उत्तराखंड कॉपरेटिव बैंक ऋषिकेश ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख 11 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग किया। गुरुवार को उत्तराखंड कॉपरेटिव बैंक के संचालक बीपीएस राणा ने एक लाख 11 हजार रुपये की राशि का चेक उप जिलाधिकारी को सौंपा।

प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया 10 लाख रुपये

कोरोना महामारी को देखते हुए यमुना निर्माण विकासनगर यात्रिक होटल विकासनगर के स्वामी नंदा सिंह नेगी और उनके पुत्र रमेश नेगी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये दान किए। चेक विधायक मुन्ना सिंह चौहान को सौंपा गया। विधायक ने कहा आज देश के हित में खड़े होकर एक सच्चे देश भक्त होने का परिचय देना चाहिए।

शांति व्यवस्था भंग की तो लगेगा एनएसए

संवाददाता देहरादून। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए हंगामे के बाद महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में कुछ लोगों ने शांतिभंग करने की कोशिश की। उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से हल्द्वानी और हरिद्वार में एक–एक कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि सौहार्द बनाए रखें, अफवाहें न फैलाएं। अब किसी ने अफवाह फैलाई या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) कहें या एनएसए ये वो कानून है जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर नकेल कसता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।